

37/11

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

124/2021/225 श्रीमती वनम रम्या देवी अज्ञे

तारीख पेशी	2021/124 हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
------------	---	--------------------------------------

21.6.21 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई । अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश एवं धारा 5 मियाद में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी०न्याया० ने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर करतो हुए अपने आदेश दिनांक 21.12.2020 के द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांटस के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का न्यायोचित आदेश प्रदान नहीं करके केवल मात्र विपक्षीगण/रेस्पो० को नोटिस जारी करने का अवैधानिक आदेश पारित किया है । उपरोक्त प्रकरण में रेस्पो० द्वारा बिना बंटवारा कराये ही विवादित भूमि पर पक्का निर्माण कार्य किया जा रहा है । जिसे वाद के निस्तारण से पूर्व रोका जाना आवश्यक था । जब सहखातेदारों के मध्य विवादित आराजी का बंटवारा नहीं हो जाता है सभी का समान अधिकार माना जाता है । इसके बावजूद अधी०न्याया० ने केवल मात्र नोटिस जारी करने के गैर कानूनी आदेश प्रदान किये है जो निरस्तनीय है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पो० को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० पेश कर निवेदन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों की पालना में कोरोना महामारी एवं लोकडाउन काल में प्रकरण को प्रस्तुत करने में किसी प्रकार का विलंब होता है तो वह क्षमा किये जाने योग्य है । न्यायहित में कोरोना महामारी एवं लोकडाउन के कारण अपील प्रस्तुत करने में जो विलंब हुआ है वह उपरोक्त सदभाविक कारण होने से क्षमा किये जाने योग्य है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया । अपीलांटस ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे सदभाविक होने से न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस/प्रार्थीगण द्वारा अधी०न्याया० के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 212 राज०काश्त०अधि० दिनांक 21.12.2020 को पेश किये जाने पर अधी०न्याया० ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये राम्मन तलब किया जिस पर अप्रार्थीगण की और से दिनांक 23.12.2020 को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की और से श्री रामदेव गुर्जर, अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया । अधी०न्याया० द्वारा दिनांक 21.12.2020 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये है । यह आदेश अंतरिम आदेश है न कि अंतिम आदेश । विधिनुसार अंतरिम आदेश के विरुद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संधारण योग्य नहीं है किन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है अधी०न्याया० के समक्ष रेस्पो० द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश हो चुका है । हम न्यायहित में पक्षकारान के समय एवं आर्थिक मितव्यता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण को इसी स्तर पर निर्णित कर अधी०न्याया० को प्रार्थना पत्र धारा 212 राज०काश्त०अधि० को 30 दिवस में निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित करना न्यायोचित समझते है ।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है

अजमेर अपील प्राधिकारी

124/21/225

राजस्थान उच्च न्यायालय - 4/3 इंदूर

तथा प्रकरण अधीन न्यायाधीशों को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थीगण/अपीलेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजकांशत/अधीन पर समयपक्षकारान को सुनकर प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में निस्तारण करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।
 निर्णय आज दिनांक 21.6.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मेघना चौधरी)
 राजस्थान उच्च न्यायालय, इंदूर
 अजमेर